

# राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

वर्ष 12 अंक 2

जुलाई—दिसम्बर 2010

1.“ जूरगेन हैबरमास सिद्धान्तकार, समीक्षक और समाजवैज्ञानिक ”—प्रोफेसर पी. एन. पाण्डेय, प्रोफेसर समाजशास्त्र, पूर्व संकाय प्रमुख, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)

हैबरमास प्रकार्यवाद, विवेचनावाद संरचनावाद और अन्तःक्रियावाद के मध्य एक विचारक के रूप में अपने को प्रस्थापित करते हैं। इनकी राय में आधुनिकता की परियोजना अभी अपूर्ण है। ऐसे में उत्तर आधुनिकता की बात करना तर्क संगत नहीं। आधुनिकता अपने द्वितीय चरण से गुजर रही है जिसमें व्यवस्था और जीव-जगत का परस्पर सम्बन्ध विघटित हुआ हो। कालान्तर में आधुनिकता के दौर में ही जब पूर्ण तार्किकता का समावेश होगा तो एक कल्याणकारी लोक व्यवस्था आविर्भूत होगी।

2.“ भारतीय ग्रामीण समाज में गुट निर्माण में जाति की भूमिका ”—डॉ. सीताराम सिंह, रीडर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, गनपत सहाय पी0जी0कालेज, सुलतानपुर (उप्र०)

गुटबन्दी भारतीय ग्रामीण सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। परम्परागत ग्रामीण समुदायों के अंतर्गत गुटों का निर्माण प्रमुखतः जाति, गोत्र एवं रक्त सम्बन्धों के आधार पर होता था किन्तु सांप्रत ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, औद्योगीकरण, नगरीकरण, कृषि के नवीनीकरण एवं व्यवसायीकरण आदि के फलस्वरूप गुट निर्माण में जाति, गोत्र एवं रक्त संबंधों के स्थान पर आर्थिक एवं राजनीतिक कारण भी महत्वपूर्ण हो गये हैं। प्रस्तुत लेख भारतीय ग्रामीण समाज में गुट निर्माण में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयास है।

3.“ आर्य का मूल अर्थ जंगली असभ्य: एक नवीन ऐतिहासिक खोज ”—डॉ० श्याम लाल सिंह देव निर्मोही, पूर्व विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, भारतीय महाविद्यालय, फरुखाबाद, सम्प्रति— प्राचार्य ए.वी. महाविद्यालय, गुरुसहायगंज, कन्नौज (उ.प्र.)

अभी तक इतिहासकारों एवं अन्य विद्वानों द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि आर्य श्रेष्ठ थे, वेदों के रचनाकार थे और विजेता बनकर भारत में आए थे। प्रस्तुत लेख में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि भारत में योरोपीय प्रदेशों से आने वाले आर्य जंगली एवं असभ्य थे। वे भारत में विजेता बनकर नहीं अपितु शरणार्थी बनकर आये

4.“ भारतीय समाज में परम्परा और आधुनिकता की स्थितियाँ—समाजशास्त्रीय विश्लेषण”—डॉ० मीरा सिंह, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, आगरा कालेज, आगरा (उ.प्र.)

प्रस्तुत लेख में भारतीय समाज में परम्परा एवं आधुनिकता की स्थितियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है। इस आलेख में यह स्थापित किया गया है कि विश्व में जहाँ कहीं भी आधुनिकता का प्रवेश हुआ वहाँ, आधुनिकता और परम्पराओं में द्वन्द्व हुआ है। भारतीय समाज इसका अपवाद नहीं है। यहाँ भी आधुनिकता के श्री गणेश के साथ ही परम्पराओं ने सदैव अपनी निरन्तरता और तादाम्य बनाये रखने के लिये

अथक प्रयास किया है। वस्तुतः परम्परायें सहजता से मरती नहीं हैं बल्कि किसी न किसी विकल्प द्वारा ये अपनी निरन्तरता को बनाये रखती हैं। निःसन्देह आधुनिकता के प्रभाव इतने अधिक हैं कि निश्चित रूप से भारतीय सामाजिक संस्कृति के कई पक्ष परिवर्तित हो गये हैं, किन्तु यह भी सच है कि परिवर्तन भारतीय संस्कृति की बुनियादी संरचना और प्रतिमान को नष्ट नहीं कर पाते हैं। भारतीय समाज में अन्तर्विष्ट नभ्यता के गुणों के परिणामस्वरूप इस समाज ने आधुनिकता के कुछ पक्षों को अंगीकार कर लिया है यद्यपि इसकी भारतीयता में कोई विशेष कमी नहीं आयी है। इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारतीय परम्पराओं ने जहाँ एक ओर अपना तादाम्य बनाये रखा है, वहाँ दूसरी ओर उसने नूतनता को भी अंगीकार किया है। लेख की यह उपलब्धि उन अध्ययन परिणामों को खण्डित करती है जिनमें यह कहा गया है कि भारतीय समाज वस्तुतः परम्परा का समाज है, इसका आधुनिकता से कोई सम्बन्ध नहीं।

**5.” के. पी. ओ.—एक नई अवधारणा ”—डा० ज्योति खरे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड)**

वैश्वीकरण के दौर में आउटसोर्सिंग पिछले एक दशक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ज्वलन्त विषय बन कर उभरा है। भारत में आई०टी० उद्योग में भी आई०टी०ई०एस० – बी०पी०ओ० क्षेत्र का व्यापक विविधीकरण हुआ है। आजकल कम्पनियां नई सेवा लाइनों की खोज में जुटी हैं और धीरे – धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ रही हैं। अतः यह ज्ञान अर्थात् नॉलेज प्रोसेज आउटसोर्सिंग (के०पी०ओ०) के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। के०पी०ओ० बिजनेस प्रोसेज आउटसोर्सिंग (बी०पी०ओ०) का विस्तार है जिसमें बी०पी०ओ० की तुलना में एक विशिष्ट क्षेत्र से अधिक ज्ञान, कुशलता, अनुसंधानात्मक व विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसमें ‘उच्च अन्त’ कार्य शामिल हैं। इसके महत्व के बढ़ने का मुख्य कारण परिचालन व्यय में कमी, प्रतिस्पर्धा में शक्ति के रूप में योगदान सेवाओं में वैल्यू एडीशन, सरकारी नीतियाँ आदि हैं। समय – समय पर किये गये अध्ययन एवं उनकी रिपोर्टों के अनुसार के०पी०ओ० उद्योग का भविष्य नौकरियों के अवसरों से भी भरा दिखाई देता है। बस जरूरत है तो और अधिक कुशलता विश्लेषणात्मकता, अनुसंधानात्मकता तथा उन्नत तकनीक पाने की है। प्रस्तुत लेख के.पी.ओ. की अवधारणा एवं इसकी सामयिक महत्ता को प्रस्तुत करने का प्रयास रहा है।

**6.” भारत में सामाजिक परिवर्तन के अभिगम—एक पुनरीक्षण ”—डॉ. (श्रीमती) अनुपमा पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)**

प्रस्तुत अध्ययन जातीय संरचना पर आधारित भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के उभरते हुए स्वरूप, प्रकृति एवं प्रवृत्तियों का विश्लेषण हैं। समसामयिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन को समझने हेतु जो पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों के द्वारा अभिगम विकसित किये गये हैं, उनकी यथार्थता और उपयोगिता की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए सम्भाव्य अभिगम की गवेषणा का भी प्रयास किया गया है, जो भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमताओं के बावजूद समाज वैज्ञानिकों एवं समाज व्यवस्था के अध्येताओं को दिशा निर्देश दे सके। विवेचन की सामग्री ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिक्षेत्रों से उद्धृत की गयी है। अतः यह प्रपत्र ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय तथ्यों पर आधारित विवेचनात्मक विश्लेषणात्मक व्याख्या है।

**7.” आपदा प्रबन्धन एवं सूचना प्रौद्यौगिकी ”—नीरज राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग, बरेली कालेज, बरेली (उ.प्र.)**

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश ने औद्योगिक क्रान्ति, हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति आदि कई दौर देखे हैं। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि सांप्रत भारत संचार क्रान्ति अथवा सूचना प्रौद्योगिक क्रान्ति के दौर से गुजर रहा है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत आपदा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करने का एक प्रयास है।

**8.” सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का योगदान”**—डॉ. वीणा तिवारी, विभागाध्यक्ष राजनीतिशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय राहतगढ़, सागर (म.प्र.)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं अद्भुत विद्वान्, स्वतंत्र विचारक, कुशल राजनीतिज्ञ, महान राष्ट्रभक्त, सामाजिक क्रान्ति एवं चेतना के जनक तथा भारत की महान विभूति थे। उन्होंने सांस्कृतिक जागरण एवं शोषण मुक्त भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत भारत में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए डॉ. अम्बेडकर के योगदान को उजागर किया गया है।

**9.”उत्तराखण्ड में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण : जनपदीय विश्लेषण ”**—प्रोफेसर अंजलि बहुगुणा, प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड), डॉ. पूनम धर्माना, प्रवक्ता (अंशकालिक), अर्थशास्त्र विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बी. जी. रेड्डी पौड़ी कैम्पस (उत्तराखण्ड)

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण जीवन स्तर को दर्शाता है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के 15 विकासखण्डों में सबसे ज्यादा जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है। कृषि मानसून पर निर्भर रहने के कारण तथा सिंचाई की अपर्याप्तता के कारण कृषि की पैदावार में कमी हुई है तथा इससे कृषकों की आय का स्तर निम्न हुआ है जिसका प्रभाव उनके जीवन स्तर पर साफ देखा जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद—पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्डवार जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण का अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

**10.” लोहिया समाजवादी शैक्षिक चिंतक के रूप में ”**—प्रोफेसर निधिबाला, प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.), संदीप मिश्र, शोध अध्येता, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

भारतीय समाज में डॉ. लोहिया का नाम एक समाजवादी, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रभक्त के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से समाजवाद को एक नयी दिशा प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी आन्दोलन जिस विखराव के रास्ते पर जा रहा था उसे लोहिया ने व्यवस्थित करके नया आयाम देने का प्रयास किया। प्रस्तुत लेख उनके समाजवादी एवं शिक्षा संबंधी विचारों के प्रस्तुतीकरण का एक प्रयास है।

**11.” महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की ओर बढ़ते कदम में नरेगा की भूमिका ”**—डॉ. माधुरी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजेन्द्र प्रसाद डिग्री कॉलेज मीरगंज, बरेली, (उ.प्र.)

किसी भी राष्ट्र के सशक्त होने की कसौटी उसकी आधी आबादी आर्थात् महिलाओं का सशक्त होना है। आज के समय में महिलाएं न केवल घरेलू उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रही हैं बल्कि आर्थिक क्रियाओं का संचालन करके घर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान कर रही हैं। इस क्षेत्र में ग्रामीण महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनरेगा के प्रारंभ वर्ष 2006 से 2009–10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जितना भी समायोजन किया गया है उसमें महिलाओं का प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है। मनरेगा में महिलाओं के लिए एक तिहाई हिस्सा रखा गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें आर्थिक

सुदृढता प्रदान करना है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका को प्रकाशित करना रहा है।

**12.“ ग्रामीण और नगरीय महिलाओं का सशक्तीकरण – एक तुलनात्मक मूल्यांकन ”**—श्रीमती शिल्पी रानी, शोध अध्येत्री, गृहविज्ञान, एन.के.वी.एम.जी. (पी.जी.) कालेज, चन्दोसी, मुरादाबाद (उ.प्र.), डॉ. बी.डी. हरपलानी, अध्यक्ष गृह विज्ञान एवं प्राचार्या एस.बी.डी. गर्ल्स (पी.जी.) कालेज, धामपुर, बिजनौर (उ.प्र.)

स्वतंत्रोपरांत भारत में शासन द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु किए गए अनेकानेक प्रयासों तथा परिवर्ती सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप न केवल नगरीय अपितु ग्रामीण महिलाएं भी सशक्तीकरण की दिशा में अभिमुखीकृत हैं। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत सशक्तीकरण के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की महिलाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

**13.“ भारत में पंचायती राज और महिला सशक्तीकरण ”**—डॉ. विजय कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, जवाहर लाल मैमोरियल पी.जी. कालेज, बाराबंकी (उ.प्र.), सुनिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, जवाहर लाल मैमोरियल पी.जी. कालेज, बाराबंकी (उ.प्र.)

भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर इसे जनता का कार्यक्रम बनाना रहा है। आज भारत में पंचायती राज के स्तर पर महिलाओं की व्यापक भागीदारी है। मार्च 2008 में पंचायती राज अधिनियम में संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को कुछ राज्यों में 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया। प्रस्तुत लेख भारत में पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के मूल्यांकन का एक प्रयास है।

**14.“ पर्वतीय क्षेत्र में महिला स्वास्थ्य पर विकास कार्यक्रमों का प्रभाव ”**—डा० ज़किया रफत, रीडर समाजशास्त्र विभाग, आर०बी०डी० गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, बिजनौर (उ.प्र.), श्रीमती इलीशिबा पॉल, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, आर०बी०डी० गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, बिजनौर (उ.प्र.)

पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं की स्वास्थ्य की दशा पुरुषों की अपेक्षा कहीं बदतर है। उनके स्वास्थ्य स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में शारीरिक स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छ जल का अभाव, धूम्रपान, आदि के साथ-साथ अपरिपक्व आयु में विवाह, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रसव का परम्परात्मक स्वरूप एवं प्रसवोत्तर उचित देखभाल का अभाव, परम्परागत चिकित्सा पद्धति में विश्वास तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत लेख पहाड़ी महिलाओं के स्वास्थ्य की इसी स्थिति को उजागर करने का प्रयास है।

**15.“ नगरीय एवं महानगरीय कालेज छात्राओं के परिवार एवं विवाह सम्बन्धी प्रतिमानों का तुलनात्मक विवेचन”**—डॉ. रवि प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश (उत्तराखण्ड), राकेश कुमार तिवारी, शोध अध्येता, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विष्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)

स्वाधीन भारत में स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों पर आधारित भारतीय संविधान के साथ-साथ, शिक्षा के प्रसार, औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव आदि के फलस्वरूप परिवार एवं विवाह की संरचना एवं स्वरूप में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत परिवार एवं विवाह संबंधी प्रतिमानों के संबंध में नगरीय एवं महानगरीय कालेजों की छात्राओं के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

**16.“ महिला कृषि श्रमिकों की परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया”**—कृ० शिखा श्रीवास्तव, शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, गनपत सहाय पी०जी०कालेज, सुलतानपुर (उ०प्र०), डॉ० सीताराम सिंह, रीडर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, गनपत सहाय पी०जी०कालेज, सुलतानपुर (उ०प्र०)

भारतीय समाज में कृषि के क्षेत्र में महिलाएं सदैव से महत्वपूर्ण योगदान करती रही हैं और वर्तमान समय में कृषि श्रमिक के रूप में वे स्वतंत्र रूप से अर्थोपार्जन कर रही हैं। किन्तु देखने में आता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते परिवार से संबंधित मामलों में निर्णय करने में उनकी सहभागिता आज भी बहुत कम है। प्रस्तुत लेख महिला कृषि श्रमिकों के परिवारों में परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी सहभागिता का आकलन करने का प्रयास रहा है।

**17.“ बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी : देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ”**—डॉ० रविशंकर कुमार चौधरी, इतिहास विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सरलता, नम्रता, सच्चाई की प्रतिमूर्ति, निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने वाले देश रत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद भारतीय इतिहास की विलक्षण एवं अद्वितीय निधि हैं। प्रस्तुत लेख उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर करने का एक प्रयास मात्र है।

**18.“ अल्पना का धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रकार्यात्मक महत्व(कुमाऊँनी साह समुदाय के विशेष संदर्भ में)”**—श्रीमती प्रेमा चौधरी, शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, डी०एस०बी० परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कुमाऊँ के साह समुदाय में पारिवारिक मंगल कार्यों, पूजा—अनुष्ठानों तथा तीज—त्योहारों व पर्वों के अवसर पर बनाई जाने वाली अल्पनाओं का धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अतिशय महत्व है। कुमाऊँ क्षेत्र में धरातलीय आलेखन तथा भित्ति चित्रांकन के विशिष्ट नमूने संपूर्ण भारत में अपने स्वरूप एवं अलंकरण में अद्वितीय हैं। प्रस्तुत लेख कुमाऊँ क्षेत्र में प्रचलित अल्पनाओं के विविध प्रकारों तथा उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रकार्यात्मक महत्व के विश्लेषण का एक प्रयास है।

**19.“ उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन की दशा और दिशाएक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ”**—डॉ० दीप्ती गुप्ता, प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग, ब्रह्मावर्त पी०जी०कालेज मन्धना, कानपुर (उ.प्र.)

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दलित आन्दोलन की दशा और दिशा को प्रारंभ से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को उजागर करने तथा दलित आन्दोलन के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण और वर्तमान में चल रहे दलित आन्दोलन के दृष्टिकोण की तुलनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

**20.“ इक्कीसवीं सदी की शिक्षा—व्यवस्था में शिक्षक सशक्तीकरण : एक दृष्टि”**—जयश्री शुक्ला, प्रवक्ता बी०एड. विभाग, सेण्ट्रल बुमेनस् कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, लखनऊ (उ.प्र.)

शिक्षा व्यक्ति और समाज के सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। कोई भी शिक्षा व्यवस्था सशक्तीकरण का सफल माध्यम तभी बन सकती है जब वह व्यक्ति को अपने समाज एवं राष्ट्र की चुनौतियों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार कर सके। इसके लिए स्वयं शिक्षकों का सशक्तीकरण आवश्यक है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत शिक्षक के सशक्तीकरण का अर्थ एवं आवश्यकता को प्रकाशित किया गया है।

**21.“ घरेलू हिंसा और भ्रूण हत्या – एक सामाजिक तथ्य ”**—डॉ० संजय खरे, विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय राहतगढ़, सागर (म.प्र.)

वर्तमान समय में घरेलू हिंसा का तात्पर्य मुख्यतः महिलाओं के प्रति हिंसा से लगाया जाता है। परम्परागत पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था, धार्मिक दृष्टि से पुत्र को अतिशय महत्व देने तथा बढ़ती हुई भौतिकवादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप दहेज के कारण वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति हिंसा में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रस्तुत लेख घरेलू हिंसा की समस्या को प्रकाशित करने का एक प्रयास रहा है।

**22. "ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता—एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"**—डॉ. गजबीर सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र, लाल बहादुर सिंह स्मारक डिग्री कालेज, गोहावर, बिजनौर (उ.प्र.)

स्वतंत्रोपरांत भारत में महिला कल्याणकारी संवैधानिक व्यवस्थाओं, योजनाओं तथा कानूनों के द्वारा उनकी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने हेतु अनेकानेक प्रयास किए गए हैं जिनसे न केवल नगरीय अपितु ग्रामीण महिलाएं भी लाभान्वित हुई हैं। आज वे पुरुषों के साथ—साथ ग्रामीण विकास में सक्रिय सहभागी बन रही हैं। प्रस्तुत लेख ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागेदारी को प्रदर्शित करने का एक प्रयास रहा है।

**23. "उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता संबंधी परिवर्तन"**—प्रतीक्षा वर्मा, प्राध्यापिका (बी0एड0), एल0एम0पी0वी0 गल्स पी0जी0 कॉलेज गोसाईगंज, लखनऊ (उ.प्र.)

शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम वह साधन है जो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। पाठ्यक्रम सामाजिक—सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को ज्ञान और क्रियाओं की ओर आकर्षित कर सके। 90 से पूर्ववर्ती दशकों में पाठ्यक्रम लैंगिक विभेद पर आधारित था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया था कि पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों में जो लिंगमूल भेद दिखाई देता है उसे समाप्त किया जाय। प्रस्तुत लेख में शोध अध्येत्री ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 6 से 8 तक की इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं हिन्दी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से अध्ययन करके विषय सामग्री में लैंगिक समानता की दृष्टि से अनेक वांछित परिवर्तनों की ओर संकेत किया है।

**24. "भारत की कामगार जातियाँ और महात्मा गांधी"**—अनिवाश कुमार, शोध अध्येता, गांधी विचार विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

प्रस्तुत लेख प्राचीन भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कामगार जातियों की उत्पत्ति, ऐतिहासिक विकास क्रम में उनकी परिवर्ती स्थिति तथा उनके संबंध में महात्मा गांधी के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

**25. "दलित महिलाओं की समाजार्थिक समस्यायें :एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण"**—डॉ. प्रतिमा गोंड, पूर्व शोध अध्येत्री, डी.ए.वी. स्नातकोत्तर कालेज, आजमगढ़ (उ.प्र.)

आधुनिक युग में धर्म निरपेक्ष शासन, उदारवादी दृष्टिकोण व संवैधानिक व्यवस्थाओं के लागू हो जाने के कारण दलित महिलाओं की सामाजिक—आर्थिक निर्योग्यतायें शिथिल तो अवश्य हुयी हैं परन्तु समाज में इनकी पकड़ अधिक कमजोर नहीं हुयी है। आज भी दलित महिलाओं के प्रति किया जाने वाला अपमानपूर्ण, उत्पीड़नात्मक व दमनात्मक व्यवहार सामाजिक दृष्टि से एक गम्भीर समस्या है जिसका समाधान तब तक सम्भव नहीं है जब तक सामाजिक परिवर्तन व्यापक रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित न हो जाय। इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र में दलित महिलाओं की सामाजिक—आर्थिक समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है।

**26. "अनुसूचित जाति के युवकों में सामाजिक परिवर्तन"**—डॉ. राम लला वर्मा, प्रधानाचार्य, बाबा भगवान दास आदर्श इंटर कालेज, बिकवाजितपुर, सुल्तानपुर (उ.प्र.)

वर्तमान भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से परम्परागत सामाजिक संरचना में संशोधन, परिमार्जन एवं पुनर्गठन हो रहा है। परम्परा से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से युवा पीढ़ी अधिक

प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में सामाजिक परिवर्तन की कुछ निर्दिष्ट दिशाओं में युवा पीढ़ी के मूल्यों एवं विश्वासों को समझना एवं इस दिशा में उनकी आवश्यकताओं को समझना अत्यावश्यक है। प्रस्तुत लेख इसी दिशा में एक प्रयास रहा है।

**27.“ भारतीय राष्ट्रीय खेल का गिरता स्तर : एक विवेचना ”—राजेश कुमार, शोध अध्येता, शारीरिक शिक्षा विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा), कुलताज सिंह, प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)**

खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। खेल—कूद से अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध का निर्माण करते हैं। हालांकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है लेकिन दिन—प्रतिदिन इसका स्तर गिरता जा रहा है। इस शोध—पत्र के माध्यम से शोधकर्ता ने राष्ट्रीय खेल के गिरते हुए स्तर की विवेचना की है तथा उसमें सुधार हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने का प्रयास किया है।

**28.“ विकास प्रक्रिया एवं उपेक्षित ग्रामीण अर्थव्यवस्था ”—कु. जानकी, शोध अध्येत्री, अर्थषास्त्र विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली (उ.प्र.)**

भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहां विकास प्रक्रिया से संबंधित आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण जनसंख्या को अभी तक वे सुविधाएं अथवा लाभ प्राप्त नहीं हो पाये हैं जो वास्तव में उन्हें प्राप्त होने चाहिए थे। प्रस्तुत लेख भारतीय विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वास्तविक विकास का मूल्यांकन करने का एक प्रयास रहा है।

**29.“ ईसाई मिशनरियों का योगदान “रुहेलखण्ड के परिप्रेक्ष्य में”(1857 से 1947 तक)”—श्रीमती अर्चना जौहरी, शोध अध्येत्री इतिहास विभाग, साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)**

‘मिशनरी’ धर्म प्रचारकों को ही नहीं अपितु उन लोगों को भी कहा जा सकता है जो स्वार्थ रहित होकर देश सेवा और मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। देश में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रस्तुत लेख रुहेलखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत 1857 से 1947 के बीच ईसाई मिशनरियों द्वारा किये गये योगदान को प्रकाशित करने का एक प्रयास है।

**30.“ नारनौल शहर की पेय जल व्यवस्था : एक भौगोलिक विश्लेषण ”—पिंकी यादव, शोध अध्येत्री, भूगोल विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा), राजेश कुमार, शोध अध्येता, शारीरिक शिक्षा, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)**

पेयजल स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है, किन्तु आज संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पूर्णतया स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत नारनौल नगर की पेयजल से संबंधित समस्या पर प्रकाश डाला गया है तथा इस समस्या के समाधन हेतु कठिपय महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

**31.“ ग्रामीण शक्ति संरचना एवं निर्धनता (कृषि मजदूरों के विशेष संदर्भ में)” —मनोज कुमार यादव, शोध अध्येता समाजशास्त्र, अग्रसेन पी.जी.कालेज, वाराणसी (उ.प्र.)**

प्रस्तुत लेख में कृषि मजदूरों में व्याप्त निर्धनता को ग्रामीण सामाजिक संरचना से सम्बद्ध किया गया है। परम्परागत शक्ति संरचना का स्वरूप वर्तमान समय में भी कुछ सीमा तक परिलक्षित होता है। इसे कृषक मजदूरों की निर्धनता में एक कारण के रूप में गिना जा सकता है। लेख के अन्तर्गत परिवर्तित परिस्थितियों में भी कृषक मजदूरों में निर्धनता की स्थिति को स्पष्ट किया गया है जो अत्यन्त गम्भीर है। यह तथ्य वर्तमान अध्ययन से प्राप्त हुआ है।

**32. पुस्तक समीक्षा**—पुस्तक का नाम—‘कल्ट, रिलीजन एण्ड सोसायटी – पोलियेन्ड्रस पीपुल ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज’, लेखक दिवंगत डॉ. गौरी शंकर भट्टपूर्व विभागाधक्ष समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.वी. कालेज, देहरादून, समीक्षक—प्रोफेसर टी.एन. मदन, प्रोफेसर समाजशास्त्र, इंसटीट्यूट ऑफ इकॉनामिक ग्रोथ, यूनीवर्सिटी ऑफ देहली, अनुवादक’ डॉ. उमाचरण, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, बरेली कालेज, बरेली (उ.प्र.)

**33. पुस्तक समीक्षा**—पुस्तक —कोरकू जनजाति, लेखक : डॉ. हरि प्रसाद जोशी, पूर्व प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय रतलाम, (म.प्र.), समीक्षक—प्रोफेसर सी.ए.ल. शर्मा, से.नि. प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, मोहल लाल सुखड़िया विश्वविद्यालयउदयपुर (राज.)

**34. पुस्तक समीक्षा**—पुस्तक—पुस्तक का नाम—‘पुलिस : जनाक्रोश के परिप्रेक्ष्य में, लेखक डॉ. निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्व प्राचार्य डी.ए.वी. पी.जी. कालेज, आजमगढ़ (उ.प्र.), समीक्षक— प्रोफेसर सुषमा मेलहोत्रा, पूर्व अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)